क्रिप्स मिशन (आलोचनात्मक परीक्षण)

कॉंग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार के संबंध वस्तुतः 1939 से ही शंका और तनाव से घिर चुके थे, लेकिन शत्रुता के स्पष्ट संबंध में यह तभी तब्दील हुआ, जब 1942 के प्रारंभ में क्रिप्स वार्ता भंग हो गयी। क्रिप्स मिशन प्रत्यक्षतः युद्ध से जुड़ा एक ऐसा प्रयास था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शांत करना चाहा था। युद्ध के कई मोर्चों पर मित्रराष्ट्र की सेना को मुँह की खानी पड़ी थी और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि युद्ध की लपटें भारत समेत संपूर्ण एशिया को अपनी चपेट में ले लेगी। मार्च 1942 में रंगून (बर्मा) का पतन हो गया। फलतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वार्ता के द्वारा अपने संबंध सुधारना चाहा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जनमत ने भी ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय को प्रेरित किया कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे तथा भारत पर अपनी पकड़ ढीली करे। रूजवेल्ट ने चर्चिल के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया था। अपनी भारत-यात्रा के दौरान चांग काई शेक ने भी भारतीयों के प्रति अपनी सहानुभूति का इजहार किया। ब्रिटिश अधिकारियों का एक समूह (1942, March-April), जिसमें क्रिप्स भी शामिल थे, इस पक्ष में था कि कॉंग्रेस के साथ ब्रिटिश सरकार का मनमुटाव समाप्त हो जाए। न चाहते हुए भी अंततः चर्चिल एक मिशन भेजने को राजी हो गया। लेकिन इनका मकसद केवल दुनिया को यह दिखाना भर था कि एक कोशिश की गयी। चर्चिल या लिनलिथगो यह कभी नहीं चाहते थे कि कॉंग्रेस के साथ कोई सुलह-समझौता हो जाए, इसकारण क्रिप्स को उन्होंने काफी समय तक अंधेरे में रखा और उन्हें अपने मंतव्य की भनक न लगने दी। कांग्रेस से अपनी वार्ता के एक चरण में तो क्रिप्स इस हद तक चले आये कि तुरंत एक राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के गठन को पेशकश प्रस्तुत कर दी और मामला केवल इस बिन्दु पर अटका हुआ था कि रक्षा-मंत्रालय पर इस मंत्रिमंडल का कितना नियंत्रण हो – किंतु अगले ही दिन उन्होंने इस संदर्भ में अपना पाँव पीछे खींच

तों के आकर

लिया, जाहिर है कि उनके अपने देश की सरकार ही उन्हें इसके लिए निर्देश दिया था।

क्रिप्स मिशन अचानक वार्तालाप के बीच में ही भंग हो गया, जैसा कि चर्चिल चाहते थे तथा राष्ट्रवादी नेता अनुमान किये बैठे थे कि कांग्रेस के नेताओं में संभवतः जवाहरलाल सबों से अधिक यह चाहते थे समझौता हो जाए। गाँधीजी तो इसके पश्चात् जूझ पड़ने की मानसिकता में दिख पड़े। उन्होंने क्रिप्स के अंतिम प्रस्तावों अर्थात् अधिशासी स्थिति युद्ध के तुरंत बाद दिये जाने की पेशकश पर प्रचंड प्रहार करते हुए कहा था कि यह एक "दिवालिया होते बैंक में भुनाने के लिए दिया गया आगे की तारीख का चेक" है। स्पष्टतः उस काल के अनेक भारतीयों की तरह गाँधीजी भी यह धारणा रखते थे कि युद्ध में ब्रिटेन की पराजय निश्चित है और 1942 ई० के युद्ध की स्थिति को देखते हुए यह कोई अनहोनी जैसी बात भी नहीं थी। क्रिप्स ने अन्य प्रस्ताव भी रखे जो राजे-रजवाड़ों के राजनीतिक भविष्य और प्रांतों के पृथक होकर रहने की इच्छा से संबंधित था। राजे-रजवाड़ों के बारे में माना जाता था कि वे संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे। भारतीय संघ का जो ढाँचा प्रस्तावित किया गया था, वह काफी ढीला-ढाला था और प्रांतों को निर्णय करने का अधिकार था कि वे चाहे तो संघ से अलग होकर रह सकते हैं। इस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस धारणा का वर्णन करते हुए कहा था कि "यह पाक के अस्तित्व की प्रथम सार्वजनिक स्वीकृति" थी।

ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बीच चल रही वार्ता के अंतिम रूप से भंग हो जाने के बाद जो एक मात्र रास्ता बच रहा था, वह था मुठभेड़ या संघर्षों का रास्ता। आर्थिक मोर्चे पर भी मूल्य-वृद्धि और युद्ध-कालीन अभावों के कारण व्यापक असंतोष फैला हुआ था। असम और बंगाल में सरकार की सर्वेसारी-नीति के अंतर्गत नौकाओं का अधिग्रहण किया गया जिससे

सरकार मलाया और बर्मा में निवास कर रहे गोरे लोगों को वहाँ से निकाल ले गयी, लेकिन अन्य भारतीय मूल के निवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इन सबों के फलस्वरूप लोगों के मन में अविश्वास और आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस परिस्थिति को और अधिक संकटपूर्ण बनाने में लोगों में बढ़ते इस भय ने भी यथेष्ट योगदान दिया कि निकट भविष्य में अंग्रेजों की पराजय होनेवाली है। वर्ष 1940 से ही गाँधीजी द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह और कॉंग्रेस का संगठन भारतीय जनमानस को संघर्ष के अगले दौर के लिए पहले से ही तैयार कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे दोनों पक्ष (सरकार तथा कांग्रेस) वर्षों से मुठभेड़ की प्रतीक्षा कर रहे हों और दोनों अपने विरोधी के सामर्थ्य को कम आँक रहे हों। युद्ध छिड़ने के तत्काल बाद, नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाला 'डिफेन्स ऑफ इंडिया आर्डिनेन्स' लाया। वर्ष 1940 में सरकार ने पूर्व-प्रहार करने की एक योजना बना ली और चुपचाप "रिक्विजिशनरी मूवमेन्ट आर्डिनेन्स" के दस्तावेज भी तैयार कर लिये थे। राष्ट्रवादियों की चुनौती से निपटने के लिए युद्धकालीन तैयारियों ने एक सुअवसर प्रदान कर दिया और सच तो यह है कि युद्ध ने एक ऐसा आवरण प्रदान कर दिया जिसकी ओट में कांग्रेस पर प्रहार करना आसान हो गया था। लिनलिथगो को चर्चिल के नेतृत्ववाली ही इंग्लैंड की सरकार का असीमित समर्थन प्राप्त था।

Scanned with CamScanner